पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या. 458

वर्ष-2016 का थाना कांड संख्या 82 से उत्पन्न, थाना-विजिलेंस, जिला-पटना

==========

अनिमेष कुमार, पुत्र - श्री भारत भूषण कुमार, गाँव-जादोपुर, थाना-हरसिद्धि, जिला-पूर्वी चंपारण के निवासी हैं।

.... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना बिहार के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना बिहार।
3. सचिव सह कानूनी विधि -परामर्शी, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना बिहार।
4. प्रधान सचिव, सतर्कता विभाग, बिहार सरकार, पटना बिहार।
5. सतर्कता जांच ब्यूरो, बिहार, पटना अपने महानिदेशक बिहार के माध्यम से।
6. महानिदेशक, सतर्कता जांच ब्यूरो, बिहार, पटना बिहार।

.... उत्तरदाता/गण

==========

 भारतीय दंड संहिता-धाराएँ 109 और 120 (बी)

 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-धाराएँ 13 (2), 13 (1) (ई)

संदर्भित मामलेः तमिलनाडु राज्य बनाम आर. सौन्दिरारासु और अन्य (2023) 6 एससीसी 768)

रिट-प्राथमिकी, आरोप पत्र, मंजूरी आदेश, संज्ञान आदेश को रद्द करने के लिए दायर-याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उसने अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक धन अर्जित किया। याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भा.दं.सं के सामान्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। - याचिकाकर्ता का तर्क है कि आय के वैध स्रोतों को ध्यान में नहीं रखा गया था और इस प्रकार याचिकाकर्ता की कुल आय की गलत गणना की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप आय के ज्ञात स्रोत से परे भारी धन के संचय का आरोप लगाया गया था।

निर्णीत-"आय के ज्ञात स्रोत" वाक्यांश का अर्थ है लोक सेवक की हैसियत से, जो कुछ भी वह अपनी सेवा से प्राप्त करता है। अन्य आय जो लोक सेवक की हैसियत से अनुमानित आय हो सकती है वह (ए) उसकी संपत्ति या (बी) उसका निवेश से नियमित रूप से प्राप्त होगी। - धारा 13 (1) (ई) का स्पष्टीकरण प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति को अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोत के रूप में परिभाषित करने का मांग करता है न कि अभियुक्त को। - आरोप-पत्र के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने के प्रारंभिक चरण में, अभियोजन पक्ष को केवल यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि अभियुक्त के खिलाफ एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया है। - दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के स्तर पर भी, अभियुक्त अपनी आय के ज्ञात स्रोतों को साबित करने के लिए दस्तावेजों के साथ नहीं आ सकता है। यह बचाव के समय केवल तभी होता है जब अभियुक्त अभियोजन मामले का खंडन कर सकता है और इस तरह का खंडन संपत्ति की प्रधानता की प्रकृति में नहीं है, लेकिन अभियुक्त को यह साबित करना चाहिए कि उसके पास आय के ज्ञात स्रोतों से गैर - अनुपातिक संपत्ति नहीं है। - रिट खारिज कर दिया गया

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या. 458

वर्ष-2016 का थाना कांड संख्या 82 से उत्पन्न, थाना-विजिलेंस, जिला-पटना

==========

अनिमेष कुमार, पुत्र - श्री भारत भूषण कुमार, गाँव-जादोपुर, थाना-हरसिद्धि, जिला-पूर्वी चंपारण के निवासी हैं।

.... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना बिहार के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना बिहार।
3. सचिव सह कानूनी विधि -परामर्शी, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना बिहार।
4. प्रधान सचिव, सतर्कता विभाग, बिहार सरकार, पटना बिहार।
5. सतर्कता जांच ब्यूरो, बिहार, पटना अपने महानिदेशक बिहार के माध्यम से।
6. महानिदेशक, सतर्कता जांच ब्यूरो, बिहार, पटना बिहार।

.... उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री संजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री शशि शेखर प्रसाद, अधिवक्ता

श्री अभय शंकर, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः मो. नादिम सेराज, सहायक लोक अभियोजक

निगरानी/सतर्कता के लिए: श्री अजित सिंह, अधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री बिबेक चौधरी

सी.ए.वी. निर्णय

तारीखः 22-03-2024

1. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है।:-

(क) दिनांक 26.08.2016 को दर्ज 2016 की सतर्कता थाना कांड संख्या 82 अन्तर्गत धारा 109 और 120 (बी) भारतीय दंड संहिता एवं।

(ख) उपरोक्त 2016 की सतर्कता थाना कांड संख्या 82 में विद्वान विशेष न्यायाधीश सतर्कता, पटना के न्यायालय में दिनांक 10.08.2022 को दाखिल आरोप पत्र संख्या 41/2022 को अपास्त करने।

(ग) अग्रिम प्रार्थना ज्ञापन संख्या 402 दिनांक 24.06.2022 के द्वारा जारी मंजूरी आदेश जो उपरोक्त प्राथमिकी 2016 की सतर्कता थाना कांड संख्या 82 को रद्द करने हेतु तथा इसे मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा मामले के तथ्यों की उचित

तरीके से सराहना किए बिना जारी किया गया है। इसके अलावा, बिहार के माननीय राज्यपाल के आदेश के तहत मंजूरी आदेश जारी किया गया है, लेकिन संबंधित फाइल/संचिका टिप्पणियों से पता चलता है कि उक्त मामले को आक्षेपित आदेश मंजूरी आदेश देने से पहले कभी भी बिहार के माननीय राज्यपाल के समक्ष नहीं रखा गया है।

(घ) यह भी प्रार्थना की जाती है कि तत्काल रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान विशेष न्यायाधीश सतर्कता, पटना को तत्काल मामले में आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया जाए, अर्थात 2016 सतर्कता थाना कांड संख्या 82 भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और 120 (बी) के तहत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत 26.08.2016 को स्थापित किया गया।

(ड) ऐसे अन्य आदेश (निर्देश) पारित करना जिनके लिए याचिकाकर्ता तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार है।

2. शुरुआत में यह उल्लेख किया जाए कि तत्काल मामले के लंबित रहने के दौरान, विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, पटना ने भा.द.वि की धारा 109 और 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया। याचिकाकर्ता ने विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, पटना द्वारा लिए गए संज्ञान के आदेश को रद्द करने का भी अनुरोध किया है।

3. याचिकाकर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा का सदस्य है। वे वर्ष 1996 में सेवा में शामिल हुए और 2014 तक उन्होंने राज्य सरकार की संतुष्टि के लिए ईमानदारी और लगन से अपने कर्तव्यों का पालन किया। वर्ष 2014 में, उन्हें जून, 2016 तक कैमूर में जिला परिवहन अधिकारी (डी. टी. ओ.) के रूप में तैनात किया गया था और इस अवधि के दौरान,

उन्होंने राज्य सरकार के लिए अभूतपूर्व सरकारी राजस्व जुटाया। याचिकाकर्ता के अथक और समर्पित कार्य के कारण। याचिकाकर्ता ने कहा कि राजनीतिक सांठगांठ रखने वाले कई असामाजिक लोग याचिकाकर्ता के दुश्मन बन गए। वर्ष 2016 में, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आई. पी. सी. के सामान्य प्रावधान के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, जो 2016 की सतर्कता पी. एस. संख्या 82 थी।

4. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप, संक्षेप में, यह था कि डी. टी. ओ., कामूर के रूप में काम करते हुए, उन्होंने अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक धन अर्जित किया। जाँच पूरा होने पर, निवेश अधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 109 और 120 बी के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) और 13 (2) के साथ पढ़ा गया।

5. याचिकाकर्ता ने एफ़. आई. आर./ प्रथम सूचना प्रतिवेदन और उसके बाद के आरोप-पत्र को इस आधार पर चुनौती दी है कि जाँच और आरोप-पत्र दिमाग का उपयोग न करने के उत्पाद हैं। जाँच अधिकारी ने जानबूझकर याचिकाकर्ता की कुल आय की गलत गणना की, जिसके परिणामस्वरूप आय के ज्ञात स्रोत से अधिक धन जमा होने का आरोप लगाया गया और अंततः यह आरोप लगाया गया कि यह राशि उसकी आय के ज्ञात स्रोत से अत्यधिक असंगत थी। तीसरा, यह याचिकाकर्ता द्वारा समर्पित किया जाता है। कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता की आय के अन्य स्रोतों पर विचार नहीं किया और झूठे आरोपों पर आरोप पत्र समर्पित किया। आरोप-पत्र में आरोप लगाया गया है कि जनवरी, 1996 से जून, 2016 के बीच की जांच अवधि के दौरान, आरोप-पत्र के अनुसार याचिकाकर्ता की कुल आय इस प्रकार थीः-

<u>आरोप पत्र के अनुसार याचिकाकर्ता की कुल आय (रुपये में)</u>

विभिन्न शीर्षों के तहत कमाई	कमाई रूपए में
वेतन के माध्यम से कमाई	45,51,621/-
कृषि आय	8,35,028/-

बीमा के माध्यम से कमाई	88,145/-
ऋण के माध्यम से कमाई	26,50,000/-
बैंक व्याज के माध्यम से कमाई	40,922/-
घर बेचने के बाद कमाई	36,00,000/-
<u>कुल</u>	1,17,65,716/-

6. याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि वर्ष 2010 में, याचिकाकर्ता ने नोएडा में 4,016,816 लाख रुपये के विचार मूल्य पर एक फ्लैट खरीदने का इरादा किया था। याचिकाकर्ता ने 13,78,416 रुपये का भुगतान किया। याचिकाकर्ता ने अग्रिम भुगतान के रूप में 13,78,416 लाख रुपये किया। उक्त फ्लैट खरीदने के लिए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता ने 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अपने पिता से लिया। व्यावहारिक रूप से, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता की आय से उक्त राशि को नहीं घटाया। इसके बाद, वर्ष 2011 में, याचिकाकर्ता ने उक्त फ्लैट को उसी विचार मूल्य पर अरविंद कुमार द्विवेदी को हस्तांतरित करना चाहा। यह राशि याचिकाकर्ता को उसकी पत्नी के खाते

में मिल गई थी। हालाँकि, याचिकाकर्ता की कुल आय की गणना करते समय जांच अधिकारी द्वारा उक्त राशि को ध्यान में नहीं रखा गया था। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि उसके पिता ने चेक के माध्यम से याचिकाकर्ता के बचत खाते में कुछ राशि हस्तांतरित की, लेकिन उसे भी याचिकाकर्ता की कुल आय में शामिल नहीं किया गया है। एन. एस. सी. पर ब्याज की गणना भी याचिकाकर्ता की आय के रूप में नहीं की गई थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के पास पूर्वी चंपारण जिले के यादवपुर गांव में 12 कथा जमीन थी, जिसे उसने विजय कुमार श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति को 4,40,000/- रुपये में बेच दिया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह संयुक्त परिवार से है। परिवार के पास पूर्वी चंपारण जिले के यादवपुर गाँव में लगभग 15 एकड़ 40 डिसमन भूमि है। याचिकाकर्ता कृषि भूमि से काफी पैसा कमाता है। सीतामढ़ी जिले के हरसिद्धि प्रखंड के सर्कल अधिकारी ने 17 फरवरी, 2022 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चेक अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की कुल कृषि आय लगभग रु. 2,51,89,125.70 होगा जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्ता की आय में उक्त राशि का आधा हिस्सा शामिल नहीं किया। याचिकाकर्ता ने मांग की कि उसकी वैध आय, जिसे जांच अधिकारी द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है, निम्नानुसार हैः-

याचिकाकर्ता की वैध आय जिसे जांच अधिकारी द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है

आय का स्रोत	राशि
याचिकाकर्ता के पिता द्वारा उसके बचत बैंक खाते में हस्तांतरित राशि सं। आईसीआईसीआई बैंक का 025001006873	रु. 4,25,000/-
याचिकाकर्ता के पिता द्वारा नोएडा में याचिकाकर्ता के फ्लैट की खरीद के लिए सीधे जे. पी. इन्फ्रा को हस्तांतरित राशि	रु. 8,36,016/-
कृषि आय	रु. 1,17,58,546.80/-
याचिकाकर्ता द्वारा अपनी कृषि भूमि बेचने के बाद अर्जित राशि	रु. 4,40,000/-
याचिकाकर्ता द्वारा एन. एस. सी. के माध्यम से अर्जित राशि	रु. 21,315/-
नोएडा के जे. पी. इन्फ्रा फ्लैट की बिक्री से प्राप्त राशि	रु. 2,00,000/-
कुल	रु. 1,35,80,877,80/-

7. याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता की पत्नी की आय की गणना करने के लिए, जांच अधिकारी ने उसकी आय का केवल कुछ हिस्सा लिया है। उनकी कुल आय की गणना जांच अधिकारी द्वारा नहीं की गई थी इसके अलावा, याचिकाकर्ता की पत्नी की कुछ वैध कमाई को जांच अधिकारी ने उसकी कुल आय की गणना करते समय छोड़ दिया है। याचिकाकर्ता आगे कहता है कि याचिकाकर्ता की पत्नी अलग-अलग वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आयकर विवरणी दाखिल करती थी, और आई. टी. आर. यह दिखाएगा कि 2002 और 2009 के बीच की अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता की पत्नी ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष

के लिए आई. टी. आर. दायर किया, और इस तरह के विवरणी के अनुसार, उस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की पत्नी की कुल आय 11,00,188 रुपये थी। हालांकि, जांच अधिकारी ने केवल एक 1531/-रुपये लिए हैं। याचिकाकर्ता की पत्नी की आय के रूप में जो उसने द्वारका में एक स्लिमिंग केंद्र से अर्जित की थी। याचिकाकर्ता की पत्नी ने वर्ष 2004 में बैंक से ऋण लेकर एक इंडिगो कार खरीदी थी, उक्त कार वर्ष 2015 में सतीश कुमार को 1,25,000-रुपये के विचार मूल्य पर बेची गई थी। उक्त राशि याचिकाकर्ता की पत्नी की कुल आय में शामिल नहीं थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता की पत्नी की वैध आय कुल मिलाकर 27, 47073/-रुपये थी। याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी की वैध कमाई जो जांच अधिकारी द्वारा छोड़ी गई है, रु। चेक अवधि के दौरान 1,64,27,940/-रुपये जाँच अधिकारी ने उक्त चेक अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का खर्च आरोप-पत्र में, जांच अधिकारी ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने बैंक खातों के माध्यम से किया गया कुल खर्च 84,31,188-रुपये विभिन्न लेन-देनों पर आधारित उसके द्वारा किए गए जांच अधिकारी द्वारा कथित खर्चों की गलत गणना की गई थी और उनके खिलाफ एक झूठा आरोप पत्र दायर किया गया है।

8. इसलिए, तत्काल रिट याचिका।

9. प्रतिवादी संख्या 5 और 6, जिनका प्रतिनिधित्व सतर्कता जांच ब्यूरो ने अपने महानिदेशक और महानिदेशक, सतर्कता जांच ब्यूरो, बिहार के माध्यम से किया है, ने जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसमें सतर्कता पुलिस उपाधीक्षक के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल रिट याचिका में लगाए गए सभी भौतिक आरोपों से इनकार किया गया है। यह विशेष रूप से उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने डी. टी. ओ., कैमूर के रूप में तैनात रहते हुए अवैध रूप से करमनसा चेक पोस्ट, कैमूर से गुजरने वाले वाहनों से पैसे एकत्र किए। सतर्कता खुफिया ब्यूरो ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

की और 5.48 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि करमनसा चेक पोस्ट, कैमूर में अपने व्यक्ति से जब्त की। जब सतर्कता अधिकारी ने अतिरिक्त धन के बारे में पूछताछ की तो डी. टी. ओ. से, वह अधिकारी को इतनी बड़ी राशि रखने के लिए उचित स्पष्टीकरण देने में असमर्थ था और उसने याचिकाकर्ता के खिलाफ छापेमारी भी की। इसके बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 409,420,467,468,471 और 120 बी के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (सी) (डी) के साथ पठित 13 (2) के तहत 2016 की सतर्कता थाना मामला संख्या 41 दर्ज की गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी श्रीमती माला सिंह की आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ 2016 का सतर्कता पी. एस./थाना मामला संख्या 82 दर्ज किया गया। जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी दोनों की सभी वैध आय के साथ-साथ संपत्ति और व्यय को ध्यान में रखा गया और यह पाया गया कि वर्ष 1996 से 2016 तक की चेक अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता की कुल आय 122,26,091-रुपये जबकि परिसंपत्तियाँ और व्यय 2,42,29,367/-रुपये। इसलिए, आय से अधिक संपत्ति 1,20,03,056/-रुपये पाया गया। जाँच पूरी होने पर, पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 109 और 120 बी के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ई) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत आरोप पत्र समर्पित किया।

10. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अन्य सभी तथ्यात्मक दावे। रिट याचिका में उत्तरदाताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

11. याचिकाकर्ता ने एक पूरक हलफनामा दायर किया है और साथ ही प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे का जवाब दिया है और वह रिट याचिका में किए गए उसी कथन को दोहराता है।

12. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री संजय सिंह ने शुरुआत में कहा कि सतर्कता थाना पटना मामला संख्या 41, दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के संबंध में, पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (2) और 13 (1) (सी) (डी) के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 420,409,467,468,471,120 बी के तहत, आज तक कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। हालाँकि, 2016 के बाद के सतर्कता पी. एस./थाना मामला संख्या 82 के संबंध में, सतर्कता जांच ब्यूरो ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया।

13. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आगे यह समर्पित किया जाता है कि न्याय के आपराधिक प्रशासन का मूल नियम यह है कि एक आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह यह दिखाने में सक्षम है कि कोई संदिग्ध परिस्थिति थी जिसके कारण प्राथमिकी और आरोप पत्र को अस्वीकार कर दिया गया था, तो याचिकाकर्ता राहत पाने का हकदार है।

14. इस तरह के परिचय के साथ, याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया है कि आरोप पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता की आय के ज्ञात स्रोत के बाहर आय से अधिक संपत्ति की राशि 1,20,03,056/-रुपये है। हालाँकि स्वयं के एक ही आरोप पर, याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन किया गया था। अनुशासनात्मक कार्यवाही में, 2016 के सतर्कता पी. एस. मामला संख्या 82 के जांच अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। अनुशासनात्मक कार्यवाही इस निष्कर्ष के साथ समाप्त हुई कि याचिकाकर्ता के पास रुपये की आय से अधिक संपत्ति नहीं थी। 1,20,03,056/- रुपये, लेकिन याचिकाकर्ता की आय से अधिक संपत्ति की राशि 19,21,992-रुपयेथी।

15. अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा तथ्य के इस तरह के निष्कर्ष को देखते हुए, स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठता है कि क्या उत्पीड़न का मामला उचित था या नहीं।

16. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील, कानून के सवाल पर, समर्पित करते हैं कि 2016 के सतर्कता पी. एस./ थाना मामला संख्या 82 की शुरुआत कानूनी रूप से अनुमत नहीं है।

17. **विनय त्यागी बनाम इरशाद अली उर्फ़ दीपक और अन्य 5 एस. सी. सी. 762** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करते हुए। याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा समर्पित किया गया कि विभिन्न रूपों में और विभिन्न चरणों में जांच का आदेश दिया जा सकता है, प्राथमिकी या शिकायत प्राप्त करने के प्रारंभिक चरण में, न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 156 (1) के प्रावधानों के अनुसार जांच का निर्देश दे सकता है। जांच निम्नलिखित प्रकार की हो सकती हैः

(i) प्रारंभिक जाँच,

(ii) आगे की जाँच,

(iii) ताजा या नए सिरे से या फिर से जांच।

18. “प्रारंभिक जाँच "वह है जो पुलिस अधिकारी को एक एफ. आई. आर./प्रथम सुचना प्रतिवेदन दर्ज करने के लिए संचालित करने का अधिकार देता है। इस तरह की जांच से ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा सकती है और यह उस जांच को अपने दायरे में लेगा जो अधिकार प्राप्त अधिकारी संहिता की धारा 156 (3) के संदर्भ में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा पारित जांच के आदेश को आगे बढ़ाने के लिए करेगा। “आगे की जाँच "वह जगह है जहाँ जाँच अधिकारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) के संदर्भ में अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर करने के बाद आगे मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करता है। यह पिछले जांच

पड़ताल की एक प्रकार का उच्चारण है। आगे की जाँच का आधार नए साक्ष्य की खोज और उसी अपराध की निरंतरता और उसी घटना या उससे संबंधित घटनाओं की श्रृंखला है। दूसरे शब्दों में, इसे "पुनर्निरीक्षण", "ताजा या नए सिरे से जांच" के पूर्ण विरोधाभास में समझना होगा। आगे की जाँच का दायरा आगे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की खोज तक ही सीमित है। इसका उद्देश्य अदालत के समक्ष सही तथ्यों को लाना है, भले ही वे प्राथमिक जांच के लिए बाद के चरण में पाए जाएं। आगे की जाँच के अनुसरण में प्रस्तुत रिपोर्ट को आमतौर पर "पूरक रिपोर्ट" के रूप में वर्णित किया जाता है। चूंकि बाद की जांच प्राथमिक जांच के पूरक के लिए है और इसका उद्देश्य है, हालांकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) के प्रावधानों में "आगे की जांच" करने या अदालत की अनुमति के साथ पूरक रिपोर्ट दायर करने की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। जांच एजेंसियों ने न केवल इसे समझा है, बल्कि इसे "आगे की जांच" करने और "पूरक रिपोर्ट" दायर करने के लिए अदालतों से अनुमति लेने के लिए एक कानूनी अभ्यास और औचित्य की प्रक्रिया के रूप में भी अपनाया है। जिन मामलों को एक कानूनी अभ्यास के रूप में समझा और लागू किया जाता है और वे पटना उच्च न्यायालय सी. आर. के कानून के मूल नियम के खिलाफ नहीं हैं। *समकालीन एक्सपोज़िशियो* के सिद्धांत की सहायता से अनुमति होगी। अन्यथा भी न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अदालत से ऐसी अनुमति लेने और किसी संदिग्ध/आरोपी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उपरोक्त रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 54 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके तहत निर्णय दियाः-

> *"54.जिस अपराध के लिए उसने पहले ही संहिता की धारा 173 (2) के संदर्भ में एक रिपोर्ट दायर की है, उसके संबंध में किसी भी जांच एजेंसी को "नए सिरे से" "नए सिरे से" या "फिर से जांच" करने का अधिकार नहीं है। इस तरह के आदेश पारित करने के लिए सशक्त उच्च न्यायालयों के आदेशों पर ही उपरोक्त जांच की जा सकती है, जिस स्थिति में उच्च न्यायालयों को पहले से की गई जांच और इस तरह*

से विद्वत मजिस्ट्रेट/दंडाधिकारी की अदालत के समक्ष दायर रिपोर्ट के भाग्य के संबंध में एक विशिष्ट आदेश पारित करना होगा। "

19. इस प्रकार, याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि जांच एजेंसी के पास 2016 का सतर्कता पी. एस./थाना मामला संख्या 82 दर्ज करके नए सिरे से जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं था। 2016 का सतर्कता पी. एस./थाना मामला संख्या 41 की कथित 5 लाख 28 हजार रु. की राशि की बरामदगी के आधार पर स्थापित किया गया था। इसलिए, आय से अधिक संपत्ति का मामला, अर्थात, 2016 का सतर्कता पी. एस./थाना मामला संख्या 82 दूसरी एफ. आई. आर./प्रथम सुचना प्रतिवेदन होने के कारण रद्द किया जा सकता है।

20. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हैं। **सालिब उर्फ़ शालू उर्फ़ सलीम बनाम यू. पी. राज्य और अन्य 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 947** *के समतुल्य* **2023 (3) पी. एल. जे. आर. एससी 389।** याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 28 से 30 का उल्लेख किया है जो नीचे दिया गया हैः-

"28. इस स्तर पर, हम कुछ महत्वपूर्ण देखना चाहेंगे। जब भी कोई अभियुक्त आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी. सी.) की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके एफ. आई. आर./प्रथम सुचना प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए न्यायालय के समक्ष आता है या आपराधिक कार्यवाही को अनिवार्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दिया जाता है कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली होती है या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफ. आई. आर./प्रथम सुचना प्रतिवेदन को

सावधानीपूर्वक और थोड़ी अधिक बारीकी से देखे। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जब शिकायतकर्ता व्यक्तिगत प्रतिशोध आदि के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक अभिवचनों के साथ प्राथमिकी/शिकायत का बहुत अच्छी तरह से मसौदा तैयार किया जाए। शिकायतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि एफ. आई. आर./शिकायत में किए गए कथन ऐसे हों कि वे कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा करें। इसलिए, न्यायालय के लिए केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा किया गया है या नहीं, केवल एफ. आई. आर./शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा। तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाहियों में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभिकथनों के अलावा मामले के रिकॉर्ड/अभिलेख से उभरने वाली कई अन्य उपस्थित परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और सावधानी के साथ पंक्तियों के बीच पढ़ने का प्रयास करे। न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 226 को केवल एक मामले के चरण तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मामले की शुरुआत/पंजीकरण के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखने का अधिकार है। उदाहरण के लिए मामला को लिया जाए। इस अवधि में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। यह ऐसी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में है कि कई प्राथमिकियों का पंजीकरण महत्वपूर्ण है, जिससे निजी या व्यक्तिगत द्वेष से बदला लेने का मुद्दा आकर्षित होता है जैसा कि आरोप लगाया गया है।

29. मामले के समग्र दृष्टिकोण में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 2022 की एफ. आई. आर./प्रथम सुचना प्रतिवेदन संख्या 175 दिनांकित 11.08.2022 जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, रद्द की जानी चाहिए। यह इतना स्पष्ट है कि जैसा कि राज्य का मानना है कि अपीलार्थी का ससुर इकबाल उर्फ़ बाला एक बहुत ही कठोर अपराधी है, उसका दामाद यानी वर्तमान अपीलार्थी जिसे पहले सूचना देने वाले के आगे के बयान में फंसाया गया है, वह भी एक अपराधी है।

30. इसके परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और इसके द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर के पुलिस स्टेशन मिर्जापुर में दर्ज 2022 की एफ. आई. आर./प्रथम सुचना प्रतिवेदन संख्या 175 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। "

21. दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल सिंह समर्पित करते हैं कि आय के ज्ञात स्रोत की आय से अधिक संपत्ति के मामले में, यदि अभियुक्त/याचिकाकर्ता प्राथमिकी को रद्द करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे स्तर पर उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ताओं द्वारा समर्पित सामग्री की जांच करने की कोई शक्ति नहीं है, इसकी तुलना प्राथमिकी और उनके जवाबी हलफनामे में जांच एजेंसी द्वारा प्रदान की गई जानकारी से करें और फिर याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए प्रत्येक व्यक्तिगत आरोप के गुण-दोष पर निर्णय दें, जो मुख्य रूप से दस्तावेजों के आधार पर खातों के ब्योरा पर निर्भर करता है।

22. अपने तर्क के समर्थन में, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के एक बहुत ही हाल के निर्णय का उल्लेख किया है। **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम थोमंद्रू हन्ना विजयालक्षी उर्फ़ टी. एच. विजयलक्ष्मी**

2021 (ई) पी. एल. जे. आर. एस. सी. 67861 के बराबर **2021 (ई) पी. एल. जे. आर. एस. सी. 67861** में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिवेदित किया गया जो **ए. आई. आर. 2021 एस. सी. 5041 के बराबर है।**

23. उपरोक्त परिस्थितियों पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को भंग करने के प्रयास में वस्तुतः एक परीक्षण आयोजित करके अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे से बहुत आगे बढ़ गया है। एफ. आई. आर./प्रथम सुचना प्रतिवेदन को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर निर्णय लेने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय केवल इस बात पर विचार कर सकता था कि क्या एफ. आई. आर./प्रथम सुचना प्रतिवेदन की सभी सामग्री जैसा कि वे खड़े हैं और उनके चेहरे पर प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध बनाते हैं या नहीं। हालांकि, उच्च न्यायालय ने बाध्यकारी सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए एक लघु परीक्षण किया, जो एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए याचिका को नियंत्रित करता था।

24. उसी बिंदु पर, वह **गुजरात राज्य बनाम दिलीप सिंह किशोरसिंह राव** के मामले में एक और निर्णय को भी संदर्भित करता हैं। **2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1294** समकक्ष **2023 (4) पी. एल. जे. आर. (एस. सी.) 225** के बराबर हैं। विद्वान उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता मुख्य रूप से उपरोक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 10 पर निर्भर करते है जो नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> *"10. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन पर विचार करने के चरण में, अदालत को इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि सामग्री जो अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाया गया है वह सत्य है और यह निर्धारित करने के लिए उक्त सामग्री का मूल्यांकन करता है कि क्या सामग्री से*

उसके अंकित मूल्य पर सामने आने वाले तथ्य, कथित अपराध के लिए आवश्यक अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। तमिलनाडु राज्य बनाम एन. सुरेश राजन, (2014) 11 एस. सी. सी. 709 में इस न्यायालय ने इस विषय पर निर्धारित कानून के पहले के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए कहा हैः

"29. हमने प्रतिद्वंद्वियों की दलीलों पर ध्यान दिया है और श्री रंजीत कुमार द्वारा दी गई दलीलें हमारी सराहना करती हैं। यह सच है कि आरोपमुक्त करने के लिए आवेदनों पर विचार करते समय, न्यायालय अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है या डाकघर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य की छान-बीन कर सकता है कि क्या लगाए गए आरोप निराधार हैं या नहीं ताकि आरोपमुक्त करने का आदेश पारित किया जा सके। यह मामूली बात है कि आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में, अदालत को इस धारणा के साथ आगे बढ़ना होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड/अभिलेख में लाई गई सामग्री सही है और उक्त सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे सामने आने वाले तथ्य उनके अंकित मूल्य पर कथित अपराध का गठन करने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। इस स्तर पर, सामग्री के संभावित मूल्य पर गौर किया जाना चाहिए और अदालत से मामले में गहराई से जाने और यह मानने की उम्मीद नहीं की जाती है कि सामग्री दोषसिद्धि की गारंटी नहीं देगी। हमारी राय में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने के लिए कोई आधार है कि अपराध किया गया है और न कि क्या आरोपी को दोषी ठहराने के लिए कोई आधार बनाया गया है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, यदि अदालत सोचती है कि आरोपी ने अपने संभावित मूल्य पर रिकॉर्ड/अभिलेख पर सामग्री के आधार पर अपराध किया होगा, तो वह आरोप तय कर सकता है; हालांकि दोषसिद्धि के लिए,

अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि आरोपी ने अपराध किया है। कानून इस स्तर पर लघु परीक्षण की अनुमति नहीं देता है। "

25. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने एक सवाल उठाया है कि क्या 2016 के सतर्कता मामले संख्या 82 में एफ. आई. आर./प्रथम सुचना प्रतिवेदन को दूसरे एफ. आई. आर. के रूप में माना जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार, याचिकाकर्ता को अघोषित धन के साथ रखा गया था, जिसकी राशि 5,28,000- रुपये और सतर्कता जांच ब्यूरो द्वारा उक्त वसूली के आधार पर, 2016 का सतर्कता थाना मामला संख्या 41 दर्ज किया गया था।

26. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में 26 जुलाई, 2018 से काफी बदलाव किया गया है। धारा 13 (1) (ए) और (बी) में निम्नानुसार कहा गया हैः

"13. लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचारः

"(1) एक लोक सेवक को आपराधिक दुराचार का अपराध करने के लिए कहा जाता है, -

(ए) यदि वह आदतन स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कानूनी पारिश्रमिक के अलावा कोई संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है, जैसा कि धारा 7 में उल्लिखित है; या

(बी) यदि वह आदतन स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो बिना किसी विचार के या किसी ऐसे विचार के लिए जो वह किसी ऐसे

व्यक्ति से अपर्याप्त है जिसे वह जानता है कि वह किसी कार्यवाही या व्यवसाय में शामिल था, या होने वाला है, या होने की संभावना है। उसके द्वारा या अपने या किसी लोक सेवक के आधिकारिक कार्यों से कोई संबंध रखने से। जिसे वह अधीनस्थ है, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे वह इस तरह से संबंधित व्यक्ति में रुचि रखने या उससे संबंधित होने के लिए जानता है; या"

27. इस प्रकार, 2016 के सतर्कता पी. एस./थाना मामला संख्या 41 के तथ्य यह थे कि याचिकाकर्ता ने कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य अवैध संतुष्टि को एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया या कि वह आदतन दूसरों से विचार किए बिना किसी भी मूल्यवान चीज़ को स्वीकार करता है।

28. हालाँकि, 2016 का सतर्कता पी. एस./थाना मामला संख्या 82 में शामिल मामला धारा 13 (1) (ई) के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित है, जो कहता हैः-

(ङ) यदि वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति अपने पद की अवधि के दौरान किसी भी समय कब्जे में है या उसके पास है, तो वह कब्जे में है जिसके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से लेखा नहीं दे सकता है, एक आर्थिक संसाधन। या **"आय के ज्ञात स्रोत से असमान संपत्ति।** "

29. राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय **तमिलनाडु राज्य बनाम आर. सौन्दिरारासु और अन्य** को **(2023) 6 एस.सी.सी. 768** में प्रतिवेदित किया गया जो 1988 के अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) में "आय" और "आय के ज्ञात स्रोत" शब्द के अर्थ और दायरे का विस्तार से उल्लेख किया है। पैरा 36 से 42 तक उक्त निर्णय के "आय के ज्ञात स्रोतों" के अर्थ को समझने के हमारे उद्देश्य के लिए बिल्कुल प्रासंगिक हैं और इसे नीचे पुनः समर्पित किया गया हैः

36. 1988 के अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के स्पष्टीकरण में 1988 के अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) में उपयोग की गई "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति को परिभाषित करने का प्रभाव है। 1988 के अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के स्पष्टीकरण में दो भाग हैं। पहले भाग में कहा गया है कि आय के ज्ञात स्रोतों का अर्थ है किसी भी वैध स्रोत से प्राप्त आय और दूसरे भाग में कहा गया है कि ऐसी रसीद को लोक सेवक द्वारा कानून, नियमों और आदेशों के प्रावधानों के अनुसार सूचित किया जाना चाहिए था।

37. एन. रामकृष्णैया बनाम ए. पी. राज्य में "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति के पहले भाग का उल्लेख करते हुए। [एन. रामकृष्णैया बनाम एपी राज्य, (2008) 17 एससीसी 83:(2010) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 454], इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पीपी./ पृष्ठ 86-87, पैरा 17)

“17. ‘...6. धारा 13 (1) (ई) [पुरानी धारा 5 (1) (ई)] में "आय के ज्ञात स्रोत" वाक्यांश का जोर स्पष्ट रूप से "आय" शब्द पर है। यह देखना प्राथमिक होगा कि लोक सेवक के लिए, आय वही होगी जो उसके कार्यालय या पद से जुड़ी होगी, जिसे आमतौर पर पारिश्रमिक या वेतन के रूप में जाना जाता है। "आय" शब्द अपने आप में लोचदार है और इसका एक व्यापक अर्थ है। जो कुछ भी आता है या प्राप्त होता है वह आय है। लेकिन, हालांकि, "आय" शब्द का व्यापक महत्व और अर्थ, इसे किसी के श्रम, या विशेषज्ञता, या संपत्ति, या निवेश से कोई संबंध नहीं रखने वाली रसीद के रूप में समझने में असमर्थ है, और आगे एक ऐसा स्रोत होने के नाते जो नियमित रूप से राजस्व प्राप्त कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। आय शब्द को समझने के लिए ये आवश्यक विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि यद्यपि प्राप्तकर्ता के हाथ में रसीद में "आय" है, लेकिन प्रत्येक रसीद आय का स्वरूप नहीं लेती है। लोक सेवक को अपनी सेवा से जो भी प्रतिफल मिलता है, वह उसकी आय की प्राथमिक वस्तु होगी। अन्य आय जो संभवतः लोक सेवक की

आय हो सकती है, वह (ए) उसकी संपत्ति, या (बी) उसके निवेश से नियमित रसीद में होगी। अप्रत्याशित लाभ, या भ्रष्टाचार अपराध के लाभ या व्यक्तियों द्वारा अनैतिक स्राव से प्राप्त रसीद प्रथम दृष्टया किसी लोक सेवक के "आय के ज्ञात स्रोत" से प्राप्त नहीं होगी। ' [**एड.**: जैसा कि एम. पी. राज्य बनाम अवध किशोर गुप्ता, (2004) 1 एस. सी. सी. 691 पृष्ठ 697, पैरा 6] "में देखा गया है।

38. उपरोक्त हमें स्पष्टीकरण के दूसरे भाग में लाता है, जिसमें इस अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है कि "ऐसी रसीद लोक सेवक द्वारा सूचित की जानी चाहिए थी" यानी लोक सेवक द्वारा किसी लोक सेवक पर लागू कानून, नियमों या आदेशों के किसी भी प्रावधान के अनुसार सूचना।

39. 1947 के अधिनियम की धारा 5 (3) के प्रावधान इसके संशोधन से पहले, 1947 के अधिनियम की धारा 5 (1) (ई) और 1988 के अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) अभी भी वही हैं, हालांकि इसके संशोधन से पहले की धारा 5 (3) को सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य (सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 464) में एक प्रक्रियात्मक धारा माना गया था। 1947 के अधिनियम की धारा 5 (3) को इसके संशोधित होने से पहले सी. एस. डी. स्वामी बनाम राज्य (सी. एस. डी. स्वामी बनाम राज्य, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 7) में व्याख्या की गई थी और यह देखा गया थाः(सी. एस. डी. स्वामी मामला [सी. एस. डी. स्वामी बनाम राज्य, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 7], ए. आई. आर. पीपी. 10-11, पैरा 5-6)"

5. उन मामलों का भी संदर्भ दिया गया था जिनमें अदालतों ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा संपत्ति पर कब्जा करने के लिए प्रशंसनीय स्पष्टीकरण दिया गया था, जो आरोप का विषय था, तो अदालत अभियुक्त को आपराधिक जिम्मेदारी से दोषमुक्त कर सकती थी। हमारी राय में, उन मामलों का इस मामले में

अपीलार्थी के खिलाफ आरोप से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि इस धारा में अभियुक्त व्यक्ति से आय के अपने ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक आर्थिक संसाधनों या संपत्ति के कब्जे के लिए "संतोषजनक लेखा" की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, एक अभियुक्त व्यक्ति बरी होने का हकदार है यदि वह संपत्ति के ईमानदार कब्जे के लिए जिम्मेदार हो सकता है जो हाल ही में चोरी की गई साबित हुई है [साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 का चित्रण (ए) देखें]। कानून का नियम यह है कि यदि अभियुक्त का प्रथम दृष्टया स्पष्टीकरण है कि वह चोरी किए गए सामान को ईमानदारी से, आया था दोषी ज्ञान का अनुमान विस्थापित हो जाता है। यह इस सुस्थापित सिद्धांत पर आधारित है कि यदि न्यायालय के मन में किसी अपराध के आवश्यक घटक के बारे में संदेह है, तो उस संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। लेकिन विधायिका ने सलाह दी है कि "संतोषजनक रूप से लेखा" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाए। "संतोषजनक" शब्द पर जोर दिया जाना चाहिए, और इस प्रकार, विधायिका ने जानबूझकर अभियुक्त पर बोझ डाला है, न केवल एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने के लिए कि वह अपनी बड़ी संपत्ति से कैसे आया, बल्कि अदालत को यह भी संतुष्ट करने के लिए कि उसका स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य था।

6. मामले के इसी पहलू पर एक अन्य तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए सबूत नहीं दिया है कि अपीलार्थी की आय के ज्ञात स्रोत क्या हैं। इस संबंध में, हमारा ध्यान जांच अधिकारियों के साक्ष्य की ओर आकर्षित किया गया था, और उस साक्ष्य के संदर्भ में, यह तर्क दिया गया था कि उन अधिकारियों ने, अभियुक्त की आय के ज्ञात स्रोतों के संदर्भ में, या यह नहीं कहा है कि वेतन ही उसकी आय का एकमात्र स्रोत था। अब, "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति में मामले की गहन जांच पर अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोतों का संदर्भ होना चाहिए। यह न तो था और न ही यह तर्क दिया जा सकता था कि "आय के ज्ञात स्रोतों" का अर्थ अभियुक्त को ज्ञात स्रोतों से है। अभियोजन पक्ष से, चीजों की प्रकृति में, किसी अभियुक्त व्यक्ति के मामलों को जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

वे मामले साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अर्थ के भीतर अभियुक्त की "विशेष रूप से जानकारी के भीतर" होंगे। अभियोजन पक्ष केवल सबूत पेश कर सकता है, जैसा कि उसने तत्काल मामले में किया है, यह दिखाने के लिए कि आरोपी को भौतिक अवधि के दौरान सरकार के तहत सेवा द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए जाना जाता था। अभियोजन पक्ष का यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि यात्रा भत्ता भी आय का एक स्रोत था, जब ऐसा भत्ता आम तौर पर संबंधित अधिकारी को उसके आधिकारिक दौरों के लिए उसके द्वारा की गई यात्राओं के आकस्मिक खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए होता है। संभवतः इसे आय का एक बहुत बड़ा स्रोत नहीं कहा जा सकता है। किसी विशेष व्यक्ति की आय का स्रोत जीवन में उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा, विशेष रूप से उसके व्यवसाय या जीवन में व्यवसाय के संदर्भ में। एक सरकारी कर्मचारी के मामले में, अभियोजन पक्ष स्वाभाविक रूप से यह अनुमान लगाएगा कि उसकी आय का ज्ञात स्रोत उसकी सक्रिय सेवा के दौरान अर्जित वेतन होगा। उनकी पेंशन या उनकी भविष्य निधि की गणना उनकी सेवानिवृत्ति के बाद ही की जाएगी, जब तक कि उनके पास अपने भविष्य निधि से उधार लेने का कोई औचित्य न हो। इसलिए हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी की आय के ज्ञात स्रोतों के बारे में उचित सबूत देने में विफल रहा है। यह हो सकता है कि अभियुक्त ने अपनी आय के कथित स्रोतों के बारे में जांच अधिकारियों को बयान दिए हों, लेकिन यह, सख्ती से, मामले में सबूत नहीं होगा, और यदि अभियोजन पक्ष देने में विफल रहा है। एक अभियुक्त व्यक्ति की आय के सभी स्रोतों का खुलासा करना, उसके लिए आय के उन अन्य स्रोतों को साबित करने के लिए हमेशा खुला रहता है जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है या साक्ष्य में नहीं लाया गया है। ”

(जोर दिया गया)

40. धारा 5 (3) को हटाए जाने और धारा 5 (1) (ई) को अधिनियमित किए जाने के बाद भी, यह न्यायालय वासुदेव रामचंद्र कैडलवार [महाराष्ट्र राज्य बनाम वासुदेव रामचंद्र कैडलवार, (1981) 3 एस. सी. सी. 199:1981 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 690] ने पाया है कि धारा 5 (1) (ई) में आने वाली "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति का एक निश्चित कानूनी अर्थ है जिसका अर्थ इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोतों से होना चाहिए न कि उन स्रोतों से जिन पर आरोपी भरोसा करता था और जिन्हें वह जानता था। इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि धारा 5 (1) (ई) अभियुक्त पर बोझ डालती है क्योंकि यह उन शब्दों का उपयोग करती है जिनके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से जवाबदेह नहीं हो सकता है। अभियुक्त की जिम्मेदारी है कि वह परिसंपत्तियों का हिसाब दे और उन्हें संतोषजनक तरीके से समझाए। तदनुसार, वासुदेव रामचंद्र कैडलवार [महाराष्ट्र राज्य बनाम वासुदेव रामचंद्र कैडलवार, (1981) 3 एस. सी. सी. 199:1981 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 690] में यह देखा गयाः(एस. सी. सी. पीपी. 204-205, पैरा 11-13)

"11. धारा 5 (3) के प्रावधान न्यायिक व्याख्या के विषय रहे हैं। सबसे पहले धारा 5 (3) के संदर्भ में "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति का अर्थ ज्ञात स्रोत" था। अभियोजन "। दूसरा सिद्धांत समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है। हालाँकि, धारा 5 (3) के तहत अभियुक्त पर लगाई गई जिम्मेदारी उचित संदेह से परे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नहीं थी, बल्कि केवल संभावना की प्रधानता स्थापित करने के लिए थी। ये अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत हैंःदेखें सी. एस. डी. स्वामी बनाम राज्य [सी. एस. डी. स्वामी बनाम राज्य, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 7]; सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य (सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 464) और वी. डी. झिंगन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। [वी. डी. झिंगन बनाम यू. पी. राज्य, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1762] विधायिका ने धारा 5 (3) के तहत साक्ष्य के नियम को समाप्त करना और लोक सेवाओं में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण धारा 5 (1) (ई) को शामिल करके लोक सेवक द्वारा आय से

अधिक संपत्ति के कब्जे को आपराधिक कदाचार के अपराध की एक प्रजाति के रूप में लेना उचित समझा।

12. अधिनियम की धारा 5 (1) (ई) में दिखाई देने वाले शब्द और अभिव्यक्तियाँ वही हैं जो पुरानी धारा 5 (3) में उपयोग की गई हैं। हालाँकि दोनों प्रावधान दो अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन उन्हें दिया जाने वाला अर्थ समान होना चाहिए। "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति का अर्थ है "अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोत"। इसी तरह, धारा 5 (1) (ई) में आने वाले "जिनके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से जवाब नहीं दे सकता" शब्दों को भी वही अर्थ दिया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 4 (1) धारा 5 (1) (ए) और (बी) के तहत आने वाले मामलों में अपराध के अनुमान का प्रावधान करती है, लेकिन हमारी राय में, इसमें धारा 5 (1) (ई) का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कारण स्पष्ट है। इस प्रावधान में अधिनियम की धारा 5 (1) (ई) में एक स्व-निहित प्रावधान शामिल था। धारा का पहला भाग अभियोजन पक्ष पर और दूसरा भाग अभियुक्त पर बोझ डालता है। जब धारा 5 (1) (ई) उन शब्दों का उपयोग करती है जिनके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से जवाबदेह नहीं हो सकता है, तो यह निहित है कि आय से अधिक संपत्ति के अधिग्रहण के स्रोतों के लिए जवाबदेह होने का बोझ ऐसे लोक सेवक पर है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि एक लोक सेवक जिस पर अपने कब्जे में आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए वह संतोषजनक रूप से लेखा नहीं दे सकता है, उसे अधिनियम की धारा 5 (1) (ई) के साथ पठित धारा 5 (2) के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि अभियोजन पक्ष आय के सभी संभावित स्रोतों को अस्वीकार नहीं करता है।

13. यह हमें अधिनियम की धारा 5 (1) (ई) के तहत सबूत के बोझ की प्रकृति और सीमा के रूप में कठिन प्रश्न पर ले जाता है। "सबूत का बोझ" अभिव्यक्ति के दो अलग-

अलग अर्थ हैं (1) कानूनी बोझ यानी अपराध को स्थापित करने का बोझ, और (2) साक्ष्य का बोझ यानी प्रमुख सबूत का बोझ। आपराधिक मुकदमे में, अभियुक्त के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए आवश्यक सब कुछ साबित करने का बोझ अभियोजन पक्ष पर होता है, और वह बोझ कभी नहीं बदलता है। इस सामान्य नियम के बावजूद कि सबूत का भार विशेष रूप से अभियोजन पक्ष पर है, कुछ अपराधों के मामले में, मुद्दे में एक विशेष तथ्य को साबित करने का भार कानून द्वारा अभियुक्त पर डाला जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में अभियुक्त पर बोझ उतना भारी नहीं है जितना कि अभियोजन पक्ष और संभावनाओं के संतुलन के प्रमाण द्वारा निर्वहन पर है। धारा 5 (1) (ई) के साथ पठित धारा 5 (2) के तहत आपराधिक कदाचार के अपराध के तत्व आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक आर्थिक संसाधनों या संपत्ति का कब्जा हैं, जिसके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से लेखा नहीं दे सकता है। आरोप की पुष्टि करने के लिए, अभियोजन पक्ष को धारा 5 (1) (ई) के तहत मामला लाने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना होगा, अर्थात्, (1) उसे यह स्थापित करना होगा कि आरोपी एक लोक सेवक है, (2) उसके कब्जे में पाए गए आर्थिक संसाधनों या संपत्ति की प्रकृति और विस्तार, (3) यह साबित किया जाना चाहिए कि उसकी आय के ज्ञात स्रोत क्या थे, यानी अभियोजन पक्ष को पता था, और (4) उसे काफी निष्पक्ष रूप से साबित करना होगा कि आरोपी के कब्जे में पाए गए ऐसे संसाधन या संपत्ति उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से असमान थे। एक बार जब ये चार तत्व स्थापित हो जाते हैं, तो धारा 5 (1) (ई) के तहत आपराधिक दुराचार का अपराध पूरा हो जाता है, जब तक कि आरोपी ऐसे संसाधनों या संपत्ति का लेखा देने में सक्षम न हो। इसके बाद आय से अधिक संपत्ति रखने का बोझ आरोपी पर संतोषजनक रूप से डाल दिया जाता है। धारा 5 (1) (ई) के तहत आय से अधिक संपत्ति के कब्जे में पाए जाने वाले लोक सेवक पर सबूत के बोझ की सीमा और प्रकृति झिंगन मामले [वी. डी. झिंगन बनाम यू. पी. राज्य, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1762] में न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण से अधिक नहीं हो सकती है। यह

परीक्षण के बाद अदालत द्वारा निर्धारित किया गया था। वूलमिंगटन बनाम लोक अभियोजन निदेशक [वूलमिंगटन बनाम लोक अभियोजन निदेशक, 1935 ए. सी. 462 (एच. एल.)] में विस्काउंट सेंकी, एल. सी. का कथन। उच्च न्यायालय ने आय के उन सभी संभावित स्रोतों को गलत साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर एक असंभव बोझ डाल दिया है जो अभियुक्त की विशेष जानकारी में थे। जैसा कि स्वामी मामले [सी. एस. डी. स्वामी बनाम राज्य, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 7] में निर्धारित किया गया है, अभियोजन पक्ष से, चीजों की प्रकृति में, किसी लोक सेवक के मामलों को जानने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जो आय के अपने ज्ञात स्रोतों यानी उसके वेतन के अनुपात से अधिक संसाधनों या संपत्ति के कब्जे में पाया जाता है। वे मामले विशेष रूप से साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के अर्थ के भीतर लोक सेवक की जानकारी में होंगे। धारा 106 में कहा गया हैः

'106. विशेष रूप से तथ्य साबित करने का बोझ ज्ञान के भीतर। – जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसके ऊपर होता है। '

इस संबंध में, वाक्यांश "सबूत का बोझ" स्पष्ट रूप से द्वितीयक अर्थ में उपयोग किया जाता है, अर्थात्, सबूत पेश करने का कर्तव्य। अभियुक्त पर डाले गए बोझ की प्रकृति और सीमा अच्छी तरह से तय की गई है। अभियुक्त सभी उचित संदेह से परे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बाध्य नहीं है। उसे बस इतना करना है कि संभावना की प्रधानता को सामने लाना है। "

(जोर दिया गया)

41. जबकि "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोतों को संदर्भित करती है, "जिसके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से लेखा नहीं दे सकता है" अभिव्यक्ति अभियुक्त पर संतोषजनक रूप से व्याख्या करने और संपत्ति के लिए लेखा देने

की जिम्मेदारी या बोझ को संदर्भित करती है। यह भार अभियुक्त पर है क्योंकि उक्त तथ्य उसके विशेष ज्ञान में हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू होती है। धारा 13 (1) (ई) का स्पष्टीकरण एक प्रक्रियात्मक खंड है जो "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति को अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोतों के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करता है न कि अभियुक्त को। स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष द्वारा की जाने वाली जाँच के तरीके और तरीके को लागू करता है और उससे संबंधित है, यह अभियोजन पक्ष की एक खुली, व्यापक और घुमावदार जाँच करने और आय के कथित स्रोतों की जाँच करने की आवश्यकता और आवश्यकता को दूर करता है जो अभियुक्त के पास हो सकता है। यह अभियोजन पक्ष की आय के कथित स्रोतों में जाने की आवश्यकता और आवश्यकता को कम करता है जो एक लोक सेवक के पास हो सकता है या संभवतः कानूनी नहीं हैं या घोषित नहीं किए गए हैं। अघोषित कथित स्रोत अपने स्वभाव से केवल अभियुक्त को ही ज्ञात होने की उम्मीद की जाती है और वे उसके विशेष ज्ञान में होते हैं। (जोर दिया गया) स्पष्टीकरण का प्रभाव "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति की मौजूदा स्थिति और समझ को स्पष्ट और सुदृढ़ करना है अर्थात यह अभिव्यक्ति अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोतों को संदर्भित करती है न कि अभियुक्त को ज्ञात स्रोतों को। स्पष्टीकरण का दूसरा भाग पी. सी. अधिनियम, 1988 के तहत जांच किए जाने वाले अभियुक्त की आय के सभी कथित/दावा किए गए ज्ञात स्रोतों का पता लगाने के लिए एक खुली या घुमावदार जांच या जांच करने की अभियोजन पक्ष की आवश्यकता और आवश्यकता को दूर करता है। अभियोजन पक्ष किसी लोक सेवक पर लागू होने वाले कानून, नियमों और आदेशों के तहत अभियुक्त द्वारा अधिकारियों को दी गई जानकारी पर भरोसा कर सकता है। अभियुक्त लोक सेवक की आय के ज्ञात स्रोतों का पता लगाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, स्पष्टीकरण का पहला भाग कानूनी/वैध स्रोतों से प्राप्त आय को संदर्भित करता है। अभिव्यक्ति का यह पहला भाग एन. रामकृष्णैया [एन. रामकृष्णैया बनाम ए. पी. राज्य,

(2008) 17 एस. सी. सी. 83 में इस न्यायालय के फैसले से स्पष्ट रूप से बताता हैः(2010) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 454]

42. इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि "आय का ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति उन शब्दों का पर्याय नहीं है "जिनके लिए लोक सेवक संतोषजनक रूप से जवाबदेह नहीं हो सकता है। " दोनों अभिव्यक्तियाँ अलग-अलग अर्थ, दायरा और आवश्यकताओं को दर्शाती हैं।

30. इस प्रकार, "आय के ज्ञात स्रोत" वाक्यांश का अर्थ है लोक सेवक, जो कुछ भी वह अपनी सेवा से प्राप्त करता है। अन्य आय जो कि लोक सेवक की अनुमानित आय हो सकती है, वह (ए) उसके संपत्ति या (बी) उसका निवेश से नियमित रूप से प्राप्त होगी।

31. याचिकाकर्ता ने एक याचिका दायर की है कि चेक अवधि के दौरान, उसने लगभग 1 करोड़ 17 लाख रुपये उनकी संयुक्त पारिवारिक संपत्ति की कृषि आय से याचिकाकर्ता यह साबित करने के लिए बाध्य है कि उसे न केवल चेक अवधि के दौरान ऐसी राशि मिली थी, बल्कि उसने अतीत और भविष्य में भी ऐसी राशि प्राप्त की थी।

32. अभिव्यक्ति के अनुसार "आय के ज्ञात स्रोत" उन शब्दों का पर्याय नहीं है जिनसे लोक सेवक संतोषजनक रूप से लेखा नहीं दे सकता है। धारा 13 (1) (ई) का स्पष्टीकरण प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो "आय के ज्ञात स्रोत" अभिव्यक्ति को अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोत के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करता है न कि अभियुक्त को।

33. इस प्रकार, धारा 13 (1) (ई) का स्पष्टीकरण किसी भी वैध स्रोत से प्राप्त आय के बारे में बताता है और ऐसी रसीद को किसी लोक सेवक पर लागू होने वाले किसी भी कानून, नियमों या आदेश के प्रावधान के अनुसार सूचित किया गया था।

34. इसलिए, यह विशेष ज्ञान के भीतर है जिसमें अभियुक्त के साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अपनी आय के स्रोतों का खुलासा करना है।

35. आर. सौन्दिरारासु (उपरोक्त) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करते हुए खुशी हुई कि धारा 239 के स्तर पर भी अभियुक्त अपनी आय के ज्ञात स्रोतों को साबित करने के लिए दस्तावेजों के साथ नहीं आ सकता है। यह बचाव के समय केवल तभी होता है जब अभियुक्त अभियोजन मामले का खंडन कर सकता है और इस तरह का खंडन संपत्ति की प्रधानता की प्रकृति में नहीं है, लेकिन अभियुक्त को यह साबित करना चाहिए कि उसके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति नहीं है।

36. आरोप-पत्र के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने के प्रारंभिक चरण में, अभियोजन पक्ष को केवल यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि अभियुक्त के खिलाफ एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया है।

37. यह उल्लेख करना अनुचित नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष में कहा गया है कि उसके पास 19.36 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति थी। अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने के योग्य नहीं है क्योंकि यह आय के ज्ञात स्रोतों के लिए आय से अधिक संपत्ति है जो मायने रखती है न कि आय से अधिक संपत्ति की राशि जो एक लोक सेवक अपने कब्जे में रखता है।

38. मैं अपने निर्णय के उपांतिम पैराग्राफ में यह दर्ज करने के लिए लालायित हूं कि आर. साउंडिरारासु (उपरोक्त) का तथ्यात्मक पहलु भी इस मामले के तथ्य के समान है। रिपोर्ट किए गए निर्णय में, प्रतिवादी संख्या 1 एक मोटर वाहन निरीक्षक था और तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता एक जिला परिवहन अधिकारी है जो मोटर वाहनों के मामले को देखता है।

39. ऊपर बताए गए कारणों से, मुझे तत्काल पुनरीक्षण में कोई योग्यता नहीं मिलती है और इसे संघर्ष में खारिज किया जाता है।

40. हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(बिबेक चौधरी, न्यायमूर्ति)

उत्तम/- स्कम

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।